स्मार्ट औद्योगिक शहर बिना हमारा काम नहीं चलेगा

वहां क्लिक करें

चंद्रजीत बनर्जी | महानिदेशक, सीआईआई

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने का भारत का हालिया नीतिगत फैसला बहुत खास है। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बदलने और खूब रोजगार पैदा करने की तैयारी है। यह नीति भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगी।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने 2023-24 में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 14 प्रतिशत का नाममात्र योगदान दिया, फिर भी इसमें 9.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र भी समान दर से बढ़ा, जिसकी जीवीए में नौ प्रतिशत हिस्सेदारी है। साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11.11 ट्रिलियन रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) के बड़े आवंटन के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक गलियारा विकास, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और एक जिला एक उत्पाद योजना जैसी सरकारी पहल शामिल है। अब 12 औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा सरकार के इसी इरादे की एक कड़ी है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत साल 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इन 12 शहर परियोजनाओं में से चार निर्माणाधीन हैं, जबकि चार आवंटन के लिए तैयार हैं। ये 12 शहर 10 राज्यों व छह प्रमुख औद्योगिक गलियारों का विस्तार करेंगे।

12 नए शहरों में हरित निर्यात को न केवल बढ़ावा देना है, बल्कि हरित मैन्युफैक्चरिंग की स्थायी व्यवस्था करने की योजना है।

यह शहर निर्माण कार्यक्रम पीएम गति शक्ति के लक्ष्यों के अनुरूप ही है। इस कार्यक्रम में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे में पांच, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में दो और विजाग-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में एक-एक शहर परियोजना शामिल है। 28,600 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नए शहर बनेंगे, तो आसपास के इलाकों को भी आर्थिक फायदा होगा।

देश के विकास के लिए राज्यों की निर्यात-क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत उत्पाद निर्माण और निर्यात के लिए बड़े प्रयास कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, डिजाइन विनिर्माण, खाद्य और पेय पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और परिधान, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, मशीनरी व उपकरण और निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों में राज्यों की निर्यात-क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन नए शहरों में बड़े निवेशकों के साथ ही छोटे निवेशकों को भी पूरी मदद करने की योजना है।

शहर निर्माण की यह पहल 1.5 ट्रिलियन रुपये की समग्र निवेश क्षमता पैदा करने की संभावना रखती है। ध्यान दें कि कुछ प्रस्तावित शहर उन राज्यों में स्थित हैं, जो पहले से ही निर्यात के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना। अच्छी बात है कि नीति में यह भी ध्यान रखा गया है कि बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कम निर्यात हिस्सेदारी वाले राज्यों को भी शामिल किया जाए। खास बात यह भी है कि यह शहर निर्माण कार्यक्रम भारत के जलवायु लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जल को फिर उपयोग लायक बनाना और कूड़ा-कचरा के सही निस्तारण की भी चिंता की गई है। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों और वॉक-टु-वर्क जैसी अवधारणाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें अक्षय ऊर्जा का भी पूरा इंतजाम रखने की योजना है। साल 2030 तक क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। हरित निर्यात को न केवल बढ़ावा देना है, बल्कि हरित मैन्युफैक्चरिंग की स्थायी व्यवस्था करने की योजना है। यदि हमने हरित उत्पादन की चिंता की, तो विश्व स्तर पर हमारे भागीदारों की भी संख्या बढ़ेगी।

जरूरी है कि नए शहरों में उच्च तकनीकी में सक्षम श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए पुख्ता बुनियादी ढांचा दिया जाए। स्मार्ट डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जाए। एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के साथ, भारत की औद्योगिक शहर परियोजनाएं निर्यात और आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)